



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, सोमवार, 15 जून, 2009 ई0

ज्येष्ठ 25, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 219/XXXVI(3)/2009/36(1)/2009

देहरादून, 15 जून, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (2) के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 पर दिनांक 15 जून, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2009 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) अध्यादेश, 2009

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2009)

[भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 17, सन् 1976) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने हेतु

अध्यादेश

वृत्ति, राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है,

अतएव, अब, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण)] (संशोधन) अध्यादेश, 2009 है।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और आरम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

'उत्तर प्रदेश' के
स्थान पर
'उत्तराखण्ड' का
पढ़ा जाना

2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त), जिसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में जहाँ-जहाँ 'उत्तर प्रदेश' आया है, वहाँ-वहाँ 'उत्तराखण्ड' पढ़ा जायेगा।

धारा 3 की उपधारा
(2) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष तथा दावों की संख्या के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार उपाध्यक्ष (न्यायिक), उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) और न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जा सकेंगे :

परन्तु यह कि अधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति रह गयी है अथवा अधिकरण के गठन में किसी प्रकार का दोष है।"

धारा 4 क की
उपधारा (7) का
प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 4 क में उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"इस अधिनियम के अधीन कार्य सम्पादन के लिये अधिकरण, उसकी न्यायपीठ और सदस्यों की बैठक देहरादून में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, होगी।"

बी०एल० जोशी,
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

No. 219/XXXVI(3)/2009/38(1)/2009
Dated Dehradun, June 15, 2009

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand [The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal)] (Amendment) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 01 of 2009)

As promulgated by the Governor and assented on 15 June, 2009

THE UTTARAKHAND [THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNAL)] (AMENDMENT) ORDINANCE, 2009

(UTTARAKHAND ORDINANCE No. 01 of 2009)

[Promulgated by the Governor in the Sixtieth Years of the Republic of India]

Further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 (Act No. XVII of 1976) (As applicable in the State of Uttarakhand) in its applicability to the State of Uttarakhand

AN

ORDINANCE

WHEREAS, the State Assembly is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand [The Uttar Pradesh Public Services (Tribunal)] (Amendment) Ordinance, 2009.

Short Title,
Extent and
Commencement

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976 (As applicable in the State of Uttarakhand), hereinafter referred to as the Principal Act, wherever the expression 'Uttar Pradesh' occurs the same shall be read as 'Uttarakhand'.

The word 'Uttar
Pradesh' to be
read as
'Uttarakhand'

3. In section 3 of the Principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

Substitution of
sub-section (2)
of section 3

"(2) The Tribunal shall consist of a Chairman and in the light of the claims and necessities Vice-Chairman (Judicial), Vice-Chairman (Administrative) and Judicial and Administrative Member may be appointed by the State Government :

Provided that no act or proceeding of the Tribunal shall be invalidated merely by reason of any vacancy in, or any defect in the constitution of Tribunal."

4. In section 4A of the Principal Act, for sub-section (7) the following sub-section shall be substituted, namely :—

Substitution of
sub-section (7)
of section 4A

"(7) The Tribunal, its Bench and members shall, for transacting business under this Act sit at Dehradun or at such other places as the State Government may direct."

B.L. JOSHI,
Governor, Uttarakhand

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.